P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VII March-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

कृषि का व्यवसायीकरण

सारांश

अर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्त्रोत तथा विदे"ाी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि का दे"ा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। दे"ा की दो तिहाई जनसंख्या कृषि व कृषि संबंधित क्षेत्रो पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। अतः कृषि की समृद्धि संपन्नता व उत्पादकता पर ही दे"ा की खु"ाहाली व समृद्धि सन्निहित है।

मुख्य शब्द : कृषि का व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण के लिए किए गए प्रयास, चुनौतियाँ, भावी रणनीति

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापक,
अर्थ"ाास्त्र विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जांजगीर

परिचय

कृषि को जब तक जीविकापार्जन का साधन समझा जाएगा तब तक कृषि लाभप्रद नहीं होगी। इसलिए आज आव"यकता है कृषि को तकनीकी एवं संसाधन सुदृढ़ कर इसे व्यवसायिक मॉडल के तौर पर विकसित किए जाने की साथ ही किसानों को आ"वस्त किए जाने की जरूरत है कि कृषि भी एक व्यवसायपरक क्षेत्र है जहॉ आर्थिक लाभ की असीम संभावनाएं है। जब तक कृषि का व्यवसायीकरण नहीं किया जायेगा तब तक किसान इसे मजबूरी का कार्य समझकर उदासीन ढंग से कार्य करता रहेगा। वर्तमान वै"वीकरण के युग में कृषि का व्यवसायीकरण एक अनिवार्य वास्तविकता है। प्रतियोगिता में बने रहने हेतु यह आव"यक है कि कृषि वस्तुओं में गुणवत्ता हो और यह तब ही संभव है जब कृषि क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में विकसित कर लाभदायक बनाया जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभावों को जानना, व्यवसायीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों एवं भावी रणनीति का अध्ययन।

अध्ययन विधि

द्वितीयक समंको पर आधारित

कृशि का व्यवसायीकरण

1. कृषि उत्पादन का मुख्य उद्दे"य विक्रय
2. अधिकतम लाभ के लिए उत्पादन
3. उपभोक्ताओ को विभिन्न आव"यकताओं और रूचि के अनुरूप उत्पादन
4. व्यवसाय प्रबंधन की अवधारणा
5. कृषकों की उघम"ाीलता

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय कृषि की यह विडम्बना रही है कि भारत में अधिका"ातः जीविका एवं गुजारे की फसल का उत्पादन होता रहा है। यदि हम जीविकोपार्जन कृषि के साथ अधिक लाभ देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि करे तो न केवल किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है, बल्कि दे"ा की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ सकती है। यद्यपि कृषि को लाभदायक बनाने हेतु निरन्तर प्रयास हुए है लेकिन हम कृषि का कोई ऐसा मॉडल विकसित नहीं कर पाए है जिससे किसानों को कृषि में रोजगार अथवा लाभ का लक्ष्य दिखाई दे।

वर्तमान वै"वीकरण के युग में कृषि का व्यवसायीकरण एक अनिवार्य आव"यकता है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए यह आव"यक है कि कृषि वस्तुओं में गुणवत्ता हो और यह तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में विकसित कर लाभ का धंधा बनाया जाए। कृषि के व्यवसायीकरण से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि सहायक उद्यमों का भी विकास होता है।

अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास तथा गरीबी निवारण की दृष्टि से कृषि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु इसकी विकास दर अन्य क्षेत्रो के मुकाबले धीमी है। जिसका मुख्य कारण है– आधुनिकीकरण, शोध का अभाव एवं अपर्याप्त सार्वजनिक निवे"ा। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो में आर्थिक विकास को लम्बे समय तक बनाए रखने में सक्षम, जीवन्त गति"ाील एवं व्यवसायिक कृषि आव"यक शर्त है।

स्वतंत्रता के प"चात् ही दे"ा में कृषि का सर्वागींण विकास करने व किसानों की आर्थिक द"ाा में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रमों, नीतियों व योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्ष 1949 में तत्कालीन खाद्यान्न संकट के निवारण हेतु अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन का सूत्रपात किया गया। 1960–61 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की दि"ाा में कदम बढ़ाते हुए भूमि सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगान व भू–जोंतो की अधिकतम सीमा, का"तकारों की सुरक्षा, चकबंदी जैसे प्रभावी कार्यक्रम अपनाए गए।

कृषि विकास में वित्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने किसानों को उचित ब्याज दरों पर, सही समय पर ऋण उपलब्धता सुनि"चत करने के लिए संस्थागत साख, व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान की। इसके लिए सहकारी ऋण व्यवस्था, बैंको के राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना जैसे प्रभावी कदम उठाये गयें। वर्ष 1950–51 में कृषि साख में संस्थागत साख का योगदान मात्र 3.1 प्रति"ात था, जो वर्तमान में बढ़कर 55 प्रति"ात से अधिक हो गया है। किसानों को आसानी स अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1998–99 में 'किसान क्रेडिट योजना' प्रारंभ की गई। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी नाबार्ड किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रयासरत है। ग्राम आधारित विकास फंड की स्थापना गॉवों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु की गई जिससे कृषि विकास को सुनि"चत किया जा सके।

बिचौलियों के जाल से किसानों को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार ने नियंत्रित मंडियों के विस्तार, कृषि उपज के श्रेणीकरण व प्रभाणीकरण माल गोदामों की व्यवस्था बाजार एवं मूल्य संबंधी सूचनाओं का प्रसारण व सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान इस दि"ाा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सरल व सुचारू बनाने हेतु गांवो को निकटवर्ती शहरों से जोड़ने हेतु भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण–सड़कों के निर्माण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युतीकरण व दूरसंचार विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। जिससे कृषि विकास हेतु आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा सके।

1960 के द"ाक के मध्य में दे"ा में हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई तथा काफी हद तक दे"ा खाद्यानों के दृष्टिकोण से आत्म निर्भर बन गया। कृषिगत पदार्थों का अति उत्पादन होने के कारण उपज के मूल्यों को गिरने से रोकने तथा किसानो के हितो को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा कृषिगत आगतों की लागते किसानों के लिए उचित प्रतिफल को दृष्टिगत रखते हुए, न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार चाय, कॉफी, रबर व तम्बाकू के मूल्य में उच्चावचन को नियंत्रित करने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। इस योजना से 4 हेक्टेयर तक ही जोतों के किसान लाभान्वित हो सकते है, वर्तमान में इस योजना से लगभग 3.42 लाख कृषक लाभान्वित हो चुके है।

सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि व आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1973 मे 'फसल बीमा योजना' परीक्षण के तौर पर क्रियान्वित की गई। तत्प"चात् वर्ष 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, जो वर्ष 1999–2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। बागवानी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार मे राष्ट्रीय बागवानी, मि"ान 2005–06 में प्रारंभ किया। इसी के कारण भारत वि"व में नारियल, सुपारी, काजू, अदरक, हल्दी व काली मिर्च के सबसे बड़े और फल तथा सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान प्राप्त कर सका है।

कृषि के व्यवसायीकरण के लिए किए गए प्रयास

दे"ा के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के अनुसार– ''सब कुछ इंतजार कर सकता है मगर कृषि नहीं।''

कृषि के व्यवसायीकरण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गय

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007

सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारि"ाों को मानते हुए तथा राज्य सरकारों से पराम"ार्ा करने के बाद राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 को अपनाया। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है –

1. किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित करना।
2. किसानों को उचित ब्याज दरो पर वित्तीय सेवाएं समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
3. कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को समुचित महत्व प्रदान करना।
4. गाँवो में कृषक परिवार के साथ उत्पादक परिसंपत्ति सुनि"चत करना।
5. जैव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय और ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर पर्याप्त ध्यान देना।
6. राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली को अपनाना।
7. कु"ालतापूर्वक जल का उपयोग।
8. महिलाओं के लिए ि"ा"ाुसदन, बाल सेवा केन्द्र तथा पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करना।
9. पूरे दे"ा में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रभावी रूप से कार्यान्वित करना।
10. लघु कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए गुणवत्ता के बीज मृदा किस्म में सुधार करना।
11. विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए फार्म स्कूल स्थापित करना।
12. नीति कार्यान्वयन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन।

नई राष्ट्रीय कृषि नीति

1. सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

2. किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार।
3. कृषि संबंधी मामलों में स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि।
4. राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु अधिक संसाधनों के आबंटन की संस्तुति।
5. मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजे"ान फंड का सुझाव।
6. सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड का सुझाव।
7. सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग के गठन का सुझाव।

व्यापारिक फसलों का उत्पादन

भारतीय कृषि की यह विडम्बना रही है कि भारत में अधिका"ातः आजीविका की फसलों का उत्पादन होता रहा है। अगर हम जीविकोपार्जन कृषि के साथ अधिक लाभ देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि करे तो किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इन व्यापारिक फसलों में मुख्य रूप से सम्मिलित है– चाय कॉफी, मसाले, गन्ना, बागवानी आदि। इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर कृषि को व्यवसायिक मॉडल के तौर पर विकसित किया जा सकता है।

जैविक खेती

जैविक खेती करके अच्छी फसल पाई जा सकती है। कुदरती पोषण से जमीन की उर्वर क्षमता बनी रहती है। जैविक खेती से तैयार खाने की चीजों में जिंक और आयरन जैसे खनिज तत्व बडी मात्रा में मौजूद रहते है।

जड़ी–बुटी की खेती

कृषि के व्यवसायीकरण के अंतर्गत अब किसानों को जड़ी बूटी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चुनौतियाँ –

1. निवे"ा वितरण और स्थानीय कृषि प्रणाली की दुर्बलता।
2. गैर कृषि क्षेत्र में सीमित रोजगार के अवसर।
3. बाजार में पूंजी निवे"ा और नए अवसरों से उत्पन्न होने वाले लाभ को साझा करने में कृषक समुदाय वि"ोष रूप से लघु और सीमांत कृषकों को सम्मिलित करने की चुनौती।
4. विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति एवं म"ाीनो की अत्यधिक कीमतें।
5. कम आय व छोटी जोत।
6. मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी।
7. सिंचाइ हेतु पानी की अनुपलब्धता।
8. बड़े कृषकों पर निर्भरता।
9. मंडी से दूरी, तकनीकी से अपरिचित, प्रबंधन में अकु"ालता।

भावी रणनीति

कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते है– सरकार द्वारा ग्रामीण जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे– ग्रामोण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजारो में व्यापक निवे"ा से कृषि को लाभकारी बनाया जा सकता है। कृषि वित्त की सुविधा लघु व सीमांत कृषकों को रियायती दरो पर उपलब्ध करानी चाहिए। जिससे आव"यक उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा कृषि उपकरण क्रय कर सके। सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए। जिससे कृषक अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सके। भूमि सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। का"तकारी कानूनो के प्रति उदार नीति अपनाने से भूमि को पट्टे पर देना आसान बनाया जा सकता है। इससे कृषि में प्रौद्योगिकी प्रवाह बढ़ाने में सुविधा होगी। साधारण कृषि उपकरणों की खरीद के लिए दी गई सुविधाओं के अतिरिक्त बड़ी–बड़ी फार्म म"ाीनरी, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर आदि को सरकार की ओर से किराए पर दिया जाना चाहिए। सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्पादकता में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कृषक उत्पादक व निर्यातक तथा उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया जा सके। अधिकतम उत्पादकता प्राप्त प्रगति"ाील कृषकों द्वारा अपनाई गई पायलट परियोजना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षत्रो से बाजार लिंक को मजबूत किया जाए। ग्रामीण आधारभूत ढाचे को मजबूत किया जाए। वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि की जाए, शोध एवं विकास में उच्च निवे"ा को प्राथमिकता दी जाए। अनुबंध कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। नई तकनीक का प्रयोग व विविध उन्नत कृषि प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

बदलते परिवे"ा में कृषि की लागत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में किसानो की समृद्धि के लिए कृषि का व्यवसायीकरण बेहद जरूरी है। तीव्र औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विलुप्त हो रहा है। इस दृष्टिकोण से भी कृषि की व्यवसायिकता का महत्व बढ़ जाता है। पिछले लगभग 20 वर्षो में खाद, कीटना"ाकों, सिंचाई, अनुसंधान, प्रसार आदि पर बहुत खर्च करने के बावजूद उत्पादकता वृद्धि दर में वांछित वृद्धि नही लाई जा सकी है। यह किसाना के लिए एक बड़ा संकट है। इस संकट से निपटने के लिए ही केन्द्र सरकार की ओर से भी कृषि के व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कृषि व्यवसायिकता को प्रोत्साहन देने के लिए इन दिनों मिश्रित खेती का चलन बढ़ा है।

किसानो को अनाज के साथ ही बागवानी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इससे कृषि जोत में तेजी से आ रही गिरावट को रोका जा रहा है। साथ ही कृषि को लाभदायक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से किसानों को समृद्ध बनाने की दि"ाा में निरन्तर प्रयास जारी है। नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूह के माध्यम से बटाई पर खेतो करने वाले भूमिहीन किसानो एवं कृषि मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।

कृषि व्यवसायिकता के अंतर्गत ''मिट्टी जांचो और खाद डलो'' अभियान भी चलाया जा रहा है। अर्थात् जिस मिट्टी में जितनी खाद की जरूरत है उतनी ही पड़नी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की जांच पर वि"ोष जोर दिया जा रहा है। बदलते वक्त के साथ कृषि के

स्वरूप में भी परिवर्तन आज दुनिया भर के कृषकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में आव"यक है कि कृषक बदलते वक्त के अनुसार खुद को ढाल ले और उसी के अनुरूप कृषि करें। बेहतर मुनाफे के लिए कृषि उत्पादन से लेकर हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के गुण सीखना आज किसानो की जरूरत बन चुका है।

आज किसान को मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत है– पूंजी और तकनीक। दे"ा मे कृषि की नई तकनीक एवं नवप्रवर्तन करने वाले लघु सीमांत कृषकों के अनुभवो से दूसरे लोगों को जरूर सबक लेना चाहिए। गोरखपुर की रामरती देवी को उनके मिश्रित खेती के हुनर के लिए जाना जाता है। वर्ष भर में वे अपने एक एकड़ के रकबे में 32 फसलें लेती है जो कि एक मिसाल है। खेती के साथ प"ाुपालन, बागवानी, मत्स्यपालन, मिश्रित खेती करके मुनाफा कमाया जा सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। अब यह आव"यक है कि कृषि को एक व्यवसायिक मॉडल की तरह सरकारी तौर पर प्रस्तुत किया जाए। किसानों को इस बारे में आ"वस्त करने की जरूरत है कि कृषि भी एक व्यवसाय है और इसमें आर्थिक लाभ की असीम संभावनाएं है। इसके लिए जहॉ कृषकों को व्यवसायिक कृषि हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वहीं सरकार द्वारा सिंचाई प्र"िाक्षण, संसाधन उपलब्धता, शोध अनुसंधान में मदद से कृषि को लाभदायक बनाया जा सकता है।

संदर्भ

1. योजना – अगस्त 2006, मार्च 2009, जनवरी 2011, अक्टूबर 2011,जनवरी 2012 ,जनवरी 2013 जून 2014,जनवरी 2015
2. करूक्षेत्र –दिसम्बर 2000, अगस्त 2005, जुलाई 2008, फरवरी 2009, जुलाई 2010, जुलाई 2011, दिसम्बर 2011, जनवरी 2012, नवम्बर 2014, जनवरी 2015